Social Justice Union

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, रविवार 19 सितंबर 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 350

अभिनेता सोनू सूद और सहयोगियों ने 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी की : आयकर विभाग

नई दिल्ली (आरएनएस)। ताबड़तोड़ रेड का सामना कर रहे अभिनेता सोनू सूद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और उनसे जुड़े परिसरों पर दो दिनों की छापेमारी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शनिवार को कहा कि सोनू सूद के खिलाफ 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। आयकर विभाग ने कहा कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के उल्लंघन के अलावा, अब तक सोनू सूद और उनके सहयोगियों द्वारा 20 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। बता दें कि आयकर विभाग ने अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ कथित कर चोरी मामले में शुक्रवार को मुंबई, नागपुर और जयपुर में उनके कई परिसरों पर छापेमारी की थी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि अभिनेता और उनके सहयोगियों के परिसरों की तलाशी के दौरान कर चोरी से संबंधित आपत्तिजनक सबूत मिले हैं। सीबीडीटी ने कहा कि अभिनेता ने फर्जी संस्थाओं से फर्जी और असुरक्षित ऋण के रूप में बेहिसाब पैसे जमा किए। आयकर विभाग ने मुंबई में सोनू सूद के विभिन्न परिसरों के साथ-साथ लखनऊ स्थित ग्रुप रियल एस्टेट समूह में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था। दो दिनों में मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली और गुरुग्राम में कुल 28 परिसरों की तलाशी ली गई।

सीबीडीटी ने कहा कि अब तक की जांच में 20 ऐसी प्रविष्टियों के उपयोग का पता चला है, जिनके प्रदाताओं ने फर्जी आवास प्रविष्टियां देने की शपथ ली है। उन्होंने नकद के बदले चेक जारी करना स्वीकार किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां, पेशेवर प्राप्तियों को कर चोरी के उद्देश्य से अकाउंट में ऋण के रूप में छिपाया गया है। यह भी पता चला है कि इन फर्जी ऋणों का इस्तेमाल निवेश करने और संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया है।

आईटी विभाग ने अभिनेता सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन में विदेशी धन के लेन देन में कानून का उल्लंघन पाया है। सीबीडीटी ने कहा कि फाउंडेशन ने 1 अप्रैल, 2021 से अब तक 18.94 करोड़ रुपये का चंदा इकट्ठा किया है, जिसमें से उन्होंने विभिन्न राहत कार्यों के लिए करीब 1.9 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि शेष 17 करोड़ रुपये बैंक में फाउंडेशन के बैंक अकाउंट में बगैर इस्तेमाल के पाए गए हैं। सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा कि ऐसा देखा गया है कि चैरिटी फाउंडेशन ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर (विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम) एफसीआरए नियमों का उल्लंघन करते हुए विदेशी दानदाताओं से 2.1 करोड़ रुपये की राशि भी जुटाई है।

महत्वपूर्ण एवं खास

असम के राज्यपाल मुखी ने संभाला नागालैंड के राज्यपाल का भी कार्यभार

कोहिमा (आरएनएस)। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने यहां राजभवन के डॉ. इमकोंग्लिबा एओ हॉल में नागालैंड के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्हें नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राजभवन सूत्रों के अनुसार आज गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कोहिमा पीठ के न्यायमूर्ति एस. सर्टो ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफिउ रियो, उपमुख्यमंत्री वाई पैटन, नागालैंड विधानसभा अध्यक्ष शेयरिंगैन लोंगकुमेर, अन्य मंत्री, राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में प्रो मुखी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर प्रो. मुखी ने नागालैंड के लोगों से कहा कि वह अपने कर्तव्य तथा संवैधानिक जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह ईश्वर की इच्छा है कि उन्हें इस खूबसूरत राज्य के लोगों और इसकी जीवंत संस्कृति से अवगत कराया गया है। उन्होंने नागालैंड के लोगों के प्रति अपार स्नेह और कृतज्ञता व्यक्त की।

भाजपा को झटका, बाबुल सुप्रियो टीएमसी में हुए शामिल

कोलकाता(आरएनएस)। पूर्व केंद्रीय कैबिनट मंत्री बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। बाबुल ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दिया था। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओ ब्रायन की मौजूदगी में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कुछ महीने पहले जब मोदी सरकार के कैबिनेट में फेरबदल हुआ था तो बाबुल सुप्रियों को भी हटा दिया गया था जिसके बाद उनकी नाराजगी भी सामने आई थी। आसनसोल से भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो ने उसके बाद राजनीति छोड़ने की बात कही थी। टीएमसी के पास अभी भी एक राज्यसभा सीट खाली है और सूत्रों की मानें तो टीएमसी बाबुल सुप्रियो को इसके जरिए राज्यसभा में भेज सकती हैं।

बलात्कार करने के दो दोषियों को 10-10 साल की हुई जेल

बांदा(आरएनएस)। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी पाए जाने पर दो युवकों को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक ने शनिवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (त्वरित प्रथम) के विशेष न्यायाधीश ने 14 साल की लड़की को बहला-फुसला कर अपने साथ ले जाने और उसके साथ बलात्कार किये जाने के दोषी पाए गए बलराम और छत्रपाल सिंह को शुक्रवार को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि यह घटना सात अगस्त 2012 की है। दोनों दोषी नाबालिग को सूरत शहर ले गए थे और उसके साथ कई बार बलात्कार किया था। पुलिस लड़की को आठ माह बाद बरामद कर पाई और चिकित्सा जांच में उसके गर्भवती होने का पता चला था। मिश्रा ने बताया कि अदालत ने दोषियों से वसूली जाने वाली जुर्माने की राशि से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार की सबसे बड़े फेरबदल की सिफारिश, उच्च न्यायालयों के 41 जजों के बदलाव की मांग

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में पहली बार सबसे बड़ा फेरबदल किया। दरअसल, भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के 41 न्यायाधीशों की भूमिका में बदलाव की सिफारिश की है। कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में इतनी बड़ी संख्या में नामों की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के 8 जजों को अलग-अलग उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और एचसी के 5 चीफ जस्टिस को किसी अन्य एचसी का प्रमुख बनाने की सिफारिश की गई है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस यूयू ललित, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और एलएन राव भी इस कॉलेजियम में शामिल थे। इस दौरान 28 एचसी जजों के तबादले करने की भी सिफारिश की गई है। कॉलेजियम की तरफ से दिए गए 41 नामों में 13 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और 28 जज हैं। उम्मीद की जा रही है कि सभी सिफारिशें आगे की प्रक्रिया के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय तक शनिवार को पहुंचेंगी।

कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को इलाहबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। त्रिपुरा एचसी के प्रमुख अकील कुरैशी का तबादला राजस्थान करने की बात कही गई है। ट्रांसफर किए गए 4 अन्य चीफ जस्टिस में जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी (आंध्र प्रदेश एचसी से छत्तीसगढ़ एचसी), मोहम्मद रफीक (मध्य प्रदेश एचसी से हिमाचल प्रदेश एचसी), जस्टिस इंद्रजीत महंती (राजस्थान एचसी से त्रिपुरा एचसी) और जस्टिस विश्वनाथ (मेघालय एचसी से सिक्किम एचसी) का नाम शामिल है ।

देश में 80 करोड़ को लगा कोरोना वैक्सीन का टीका

नई दिल्ली(आरएनएस)। भारत में अब तक कुल 80 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को यह जानकारी दी। देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी। इसके पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया गया था।

स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार को बताया कि कोविड 19 के खिलाफ भारत बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा है। यहां पर अभी तक कुल 80 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इस शानदार उपलब्धि के लिए पूरे देश को बधाई। इस ट्वीट के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने वर्ल्ड लारजेस्ट वैक्सीन ड्राइव हैशटैग का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि शुक्रवार को भारत में 24 घंटे के अंदर कुल 2.5 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। मंडाविया ने इसे विश्व के अध्याय में एक सुनहरा अध्याय बताया।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में दस करोड़ वैक्सीनेशन होने में 85 दिन लगे। इसके अगले 45 दिनों में यह आंकड़ा 20 करोड़ तक पहुंच गया। 20 से 30 करोड़ पहुंचने में केवल 29 दिन का समय लगा। वहीं 30 करोड़ से 40 करोड़ तक पहुंचने में देश को केवल 24 दिनों का समय लगा। मिनिस्ट्री ने बताया कि छह अगस्त को भारत ने 40 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था। इसके बाद अगले 19 दिन में 60 करोड़ और उसके बाद अगले 13 दिन में आंकड़ा 60 से 70 करोड़ तक पहुंच चुका था। 13 सितंबर तक देश में लगाए गए कुल कोरोना टीकों का आंकड़ा 75 करोड़ तक था।

कलह के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छोड़ा सीएम पद

चंडीगढ़ (आरएनएस)। पंजाब कांग्रेस में लंबी चली उठापटक के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले उन्होंने अपने करीबी विधायकों के साथ बैठक भी की और इसके बाद राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ठीक 4.30 बजे राजभवन पहुंचे और इस्तीफा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने अलावा राज्य की पूरी मंत्रिपरिषद का भी इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह जब इस्तीफा देने गवर्नर हाउस पहुंचे तो उस वक्त उनके साथ पत्नी परनीत कौर भी मौजूद थीं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को इस्तीफा सौंपने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलकर कांग्रेस आलाकमान से अपनी नाराजगी जाहिर की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैंने आज सुबह ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था। बीते एक महीने में जिस तरह से तीन बार विधायकों की मीटिंग दिल्ली और पंजाब में बुलाई गई थी, उससे साफ था कि आलाकमान को मुझ पर संदेह है। ऐसे में मैंने पद से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी अब जिसे चाहे सीएम बना सकती है। इसके अलावा उन्होंने भविष्य की राजनीति के विकल्प खुले होने की बात कहकर पार्टी छोड़ने के भी संकेत दे दिए हैं।

कैप्टन अमरिंदर की कार्यशैली से नाराज होकर 40 विधायकों ने और मंत्रियों ने पार्टी हाईकमान से शिकायत की थी। विधायकों और मंत्रियों ने कहा कि जरूरी काम के लिए भी मुख्यमंत्री से मिलना बेहद मुश्किल है। इससे पहले हरीश रावत ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा था कि प्रदेश के पार्टी विधायकों ने पार्टी हाईकमान को पत्र लिख कर विधायक दल की तत्काल बैठक बुलाने की मांग की है जिसे देखते हुए 18 सितंबर को शाम 5 बजे यह बैठक बुलाने का फैसला लिया गया है।

कैप्टन अमरिंदर ने प्रताप सिंह बाजवा, गुरप्रीत औजला समेत अनेक सांसदों और समर्थक विधायकों से बातचीत की।

इथेनॉल संयंत्रों के साथ दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए पहली ईओआई को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया

नई दिल्ली (आरएनएस)। इथेनॉल की आपूर्ति हेतु आगामी समर्पित इथेनॉल संयंत्रों के साथ दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए पहली पसंद की अभिव्यक्ति (ईओआई) को शानदार प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें 197 बोलीदाताओं ने हिस्सा लिया है। यह ईओआई 27 अगस्त को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मार्गदर्शन में तेल विपणन कंपनियों की ओर से बीपीसीएल द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो 17 सितंबर को खुली थी। वर्तमान में निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

ईओआई को सफल बनाने के लिए सभी बोलीदाताओं को धन्यवाद देते हुए और उन्हें उनके उपक्रमों के लिए शुभकामनाएं देते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि यह ईओआई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक सक्रिय कदम है। पुरी ने कहा है कि तेल कंपनियां इथेनॉल की कमी वाले राज्यों में इथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के वास्ते परियोजना समर्थकों को प्रेरित करती हैं, जिससे आने वाले वर्षों में इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य 20त्न और अधिक प्राप्त करने में राष्ट्र के लिए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है।

पिछले वर्ष 173 करोड़ लीटर इथेनॉल की खरीद की गई थी और ईएसवाई - 2019-20 के दौरान 5त्न मिश्रण प्राप्त किया गया था। चालू वर्ष ईएसवाई - 2020-21 का लक्ष्य 325 करोड़ लीटर का है, जो सम्मिश्रण को 8.5त्न तक ले जाएगा। ईएसवाई - 2020-21 के दौरान वास्तविक खरीद अब तक 243 करोड़ लीटर रही है, जिससे 8.01त्न सम्मिश्रण हासिल हुआ है।

जीएसटी और परिवहन शुल्क का अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा, इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए दिए जा रहे अन्य प्रोत्साहन इस प्रकार से हैं- दीर्घकालिक प्रत्यक्षता/कुल खरीद आश्वासन; क्षमता वृद्धि के लिए ब्याज अनुदान योजना; इथेनॉल का अंतर लाभकारी मूल्य; ईओआई की शर्तों में छूट/बैंक गारंटी में कमी की शर्तें और आपूर्ति न होने पर जुर्माने का प्रावधान तथा राज्य की सीमा के भीतर खरीद प्राथमिकता देना।

बेंगलुरु में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव बरामद, 9 साल की बच्ची की भी मौत

बेंगलुरू (आरएनएस)। एक परिवार के पांच सदस्य, जिसमें चार वयस्क और एक नौ महीने का बच्चा शामिल है, अपने घर पर मृत पाए गए। बेंगलुरु के ब्यादरहल्ली पुलिस ने इसी पुष्टि की है। सभी सदस्यों के शव क्षत-विक्षत अवस्था में मिले थे। पुलिस के मुताबिक, संभवतः चार दिन पहले इनकी मौत हुई है। आशंका जताई जा रही है कि चारों की मौत आत्महत्या से हुई है। मृतकों की पहचान भारती (51), उनकी बेटियों सिंचना (34) और सिंधुरानी (34), उनके बेटे मधुसागर (25) और एक बच्चे के रूप में हुई है। घर में दो साल की बच्ची प्रेक्षा भी मिली थी। बच्ची को अस्पताल भेजा गया है। घटना के वक्त भारती का पति शंकर घर पर नहीं था।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने कहा कि घटना का पता तब चला जब मकान मालिक ने शुक्रवार शाम को पुलिस को फोन किया। उन्होंने सूचित किया कि किरायेदारों का फोन नहीं मिल रहा है और घर पर ताला लगा हुआ है।

डीसीपी (पश्चिम) संजीव एम पाटिल ने कहा, पुलिस घर से सुसाइड नोट सहित अन्य सबूत तलाश रही है। हम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पड़ोसियों को तीन-चार दिनों के बाद भी घटना का पता कैसे नहीं चला।

करमा विसर्जन के दौरान 7 लड़कियों की पानी में डूबने से हुई मौत

लातेहार (आरएनएस)। झारखंड के लातेहार जिले के बालूमाथ में करमा विसर्जन के दौरान पानी में डूबने से 7 लड़कियों की मौत हो गई। घटना बालूमाथ थाना इलाके के शेरेगाड़ा ग्राम के मननडीह टोला की है। जानकारी के मुताबिक करमा डाल विसर्जन के दौरान 7 लड़कियां डूब गई। मृतकों की उम्र 10 से लेकर 20 वर्ष के बीच बताई जा रही है। घटना की सूचना पर बालूमाथ पुलिस मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से गांव में कोहराम मच गया है है। जानकारी के मुताबिक, मृतकों में से तीन आपस में सगी बहनें थीं। मननडीह टोला निवासी अकलू गंझू की बेटियां थीं। मृतकों में रेखा कुमारी (18 वर्ष), लक्ष्मी कुमारी (8 वर्ष), रीना कुमारी (11 वर्ष), मीना कुमारी (8 वर्ष), पिंकी कुमारी (15 वर्ष), सुषमा कुमारी (7 वर्ष), सुनीता कुमारी (17 वर्ष) शामिल हैं। सभी शेरेगाड़ा ग्राम के मननडीह टोला की रहने वाली थीं। ग्रामीणों के मुताबिक टोरी-बालूमाथ-शिवपुर रेलवे लाइन निर्माण के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में लड़कियां करमा डाल का विसर्जन करने गई थीं। इस दौरान ये हादस पेश आया। ग्रामीणों जब तक मौके पर पहुंचे और लड़कियों को बाहर निकाला, तब तक 4 लड़कियां मौके पर ही दम तोड़ चुकी थीं। बाकी तीन को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें भी मृत घोषित कर दिया। आदिवासियों का पर्व करमा शुक्रवार को धूमधाम से पूरे राज्य में मनाया गया, लेकिन लातेहार के बालूमाथ में इस दर्दनाक हादसे के चलते पर्व की खुशियां मातम में बदल गई।

मार्च 2022 तक तैयार हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे : गडकरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने घोषणा की कि सरकार दुनिया के सबसे लंबे राजमार्ग, यानी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस राजमार्ग का निर्माण कर रही है।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए, गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे 1,380 किमी लंबा होगा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) तक जाएगा, लेकिन अब, हम इसे नरीमन पॉइंट तक ले जाने की भी योजना बना रहे हैं। यह परियोजना मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी और भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। इस दौरान गडकरी ने कहा कि पहले ट्रक से मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी को तय करने में करीब 48 घंटे और कार से 24-26 घंटे लगते थे। लेकिन अब, दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी को ट्रक से 18-20 घंटे और कार से केवल 12-13 घंटे लगेंगे। उन्होंने कहा, यह राजमार्ग राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों से होकर गुजर रहा है। इससे इन क्षेत्रों का विकास होगा। लोगों के लिए रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे।

एक्सप्रेसवे दिल्ली के शहरी केंद्रों को कॉरिडोर के दिल्ली-फरीदाबाद-सोहना खंड के साथ-साथ जेवर हवाई अड्डे और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को मुंबई में एक स्पर के माध्यम से जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि गुजरात में 35,100 करोड़ रुपये की लागत से 423 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। गडकरी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के तहत राज्य में 60 बड़े पुल, 17 इंटरचेंज, 17 फ्लाईओवर और आठ रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) बनाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे पर विश्व स्तरीय परिवहन सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सड़क किनारे सुविधाओं आदि से जुड़े 33 केंद्र बनाने का भी प्रस्ताव है।